

प्रेषक,

पी०के० महान्ति,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग

देहरादून: दिनांक: 13 नवम्बर, 2007

विषय:-

केन्द्रपुरोनिधानित योजना "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" के अन्तर्गत
898 एकल/सामूदायिक नई लघु सिंचाई योजनाओं हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्र सं० 909/ल०सि०/ए०आई०बी०पी०/भारत निर्माण/2007-08 दिनांक 31.10.2007 एवं शासन के पत्र सं० 1144/11-2007-04(24)/2006 दिनांक 04.10.2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोजनागत मद में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिए स्वीकृत 898 नवीन योजनाओं हेतु रु० 6840.00 लाख (रुपये अड़सठ करोड़ चालीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश संख्या: 1144/11-2007-04(24)/2006 दिनांक 04.10.2007 में निहित शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
- 2- सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 3- धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
- 4- उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय, हस्तपुस्तिका, टैण्डर/कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
- 5- अवमुक्त की जा रही धनराशि की जनपदवार/खण्डवार फाँट स्वीकृत योजनाओं के अनुपात में की जाय।
- 6- जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाये तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
- 7- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

कमश:.....2

(2)

- 8- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग निर्धारित समयान्तर्गत तक कर लिया जायेगा और इसमें कृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- 10- ए0आई0बी0पी0 की योजनाओं पर व्यय करते समय भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- 11- विभागीय कार्य करने से पूर्व लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग की दरो पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की सस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 12- प्रत्येक योजना पर शिलापट्ट/ साईन बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जाये जिस पर योजना का नाम, योजना की लागत सहित सम्पूर्ण विवरण उल्लिखित हो।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-20 के अतर्गत लेखाशीर्षक 4702-लघु सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (90 प्रतिशत के0स0), 0104-त्वरित सिंचाई लाभ योजना-24 बृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-341(P)/XXVII-4/2007 दिनांक: 07 नवम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0 के0 महान्ति)
सचिव।

संख्या: -1340/।।-2007-04 (24)/2006/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3. वित्त विभाग (वित्त अनुभाग-4), उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री, लघु सिंचाई।
7. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल हेतु।

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।